



प्रेषक,

शैलेश कुमार तिवारी ,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बस्ती ।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद बस्तीकी 07परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपनेपत्र संख्या-1478/पू0वि0नि0 राज्यांश/2025-26, दिनांक 30.12.2025का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत जनपद बस्तीकी 07 परियोजनाओंसे संबंधित प्रपत्र यथा-यूसी/फॉम-42 आई, बी0 एम0-15 व एनेग्जर-2 एवं फोटोग्राफ एवं निरीक्षण आख्यासहितजी0एस0टी0 संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति स्तम्भ-3 में अंकित शासनादेश द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं के चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में संबंधित परियोजनाओं के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि तथा कुल 07 परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-9 में अंकितयोग रू0232.25 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न प्रस्तर-3 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्वाञ्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र	परियोजना का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई मी० में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कीधनराशि	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	मांग की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विकास खण्ड दुबौलिया में बरदिया कुवर पिच मार्ग से चपरा मार्ग के बीच का नव निर्माण कार्य।	शास०-38/2025/589पू० वि०नि०/35-1-2025/35-1099/25/2025, दिनांक 30.12.2025	900	58.89	29.45	0.09	29.35	29.35
2	विकास खण्ड परसरामपुर में ग्राम कंजा तिवारी में दौलतपुर पिच मार्ग तक पिच रोड निर्माण कार्य।	तदैव	960	58.51	29.25	0.15	29.11	29.11
3	विकास खण्ड परसरामपुर में ग्राम मदनापुर से नन्दनगर तक पिच रोड निर्माण कार्य।	तदैव	740	39.72	19.86	0.08	19.78	19.78
4	विकास खण्ड बस्ती सदर अन्तर्गत रामपुर सम्पर्क मार्ग से लटेरा भट्ठा होते हुए गोपालपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	तदैव	1950	141.79	70.90	0.70	70.19	70.19

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	विकास खण्ड गौर में बभनान सोनहा सम्पर्क मार्ग पर बेलवरिया जंगल पेट्रोल पम्प से सरदहा हरनरायन गांव तक खड़जा मार्ग का लेपन कार्य।	तदैव	1420	73.40	36.70	0.06	36.64	36.64
6	दारुदपट्टी से तेलियाडीह मार्ग लम्बाई 500 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	तदैव	500	48.45	24.23	0.24	23.98	23.98
7	जिगिना रामपुर मार्ग से बरी पोखरा से काली मंदिर पिच रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	तदैव	600	46.47	23.23	0.04	23.20	23.20
		योग	7070	467.23	233.62	1.36	232.25	232.25

(रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

3. शर्तें एवं प्रतिबन्ध :

1. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारीकी होगी तथा वे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।

4.आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

5.स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नहीं रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

6.स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

7.परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।

8.निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

9.यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

10.स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारीद्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 30प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

11.सम्बन्धित जिलाधिकारीद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, 30प्र0व 30प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

12.स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2026 तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13.परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र०शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14.मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीपरियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

15.परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

16.नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ०कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

17.स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस० पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18.उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारीउत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

19. विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय कुल ₹0232.25 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक "4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

03-पूर्वान्वल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परित्यय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त,बस्ती।
8. मुख्य विकास अधिकारी,बस्ती ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,बस्ती ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,बस्ती ।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बस्ती ।
13. अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड,बस्ती ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।